कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक
प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल

कला संपादक
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क
वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क
InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

अमित शाह दोबारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने................................ 7
श्री अमित शाह का जीवन वृत्तांत.. 9

सरकार की उपलब्धियां

कैबिनेट ने नई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को मंजूरी दी.................. 11
नौजवानों को सबसे बड़ी सौगात 'स्टार्टअप इंडिया'.............................. 13

वैचारिकी

भाजपा के भविष्य से देश का भविष्य जुड़ गया है
– **अटल बिहारी वाजपेयी**... 15

श्रद्धांजलि

वी रामाराव का निधन... 17

साक्षात्कार

कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रभारी, प. बंगाल.......................... 19

लेख

संस्कारहीन राजनीति देश के लिए घातक
– **इंजी. अरुण कुमार जैन**... 25

अन्य

पं. दीनदयाल उपाध्याय : कुशल संगठक एवं विचारक राजनेता................ 18
वाराणसी : महामना एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी............................... 22
ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक... 23
भाजपा प्रदेश अध्यक्षों का निर्वाचन... 24
राज्यों से समाचार.. 29

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को

वसंत पंचमी

की हार्दिक शुभकामनाएं!

फेसबुक

सोशल मीडिया से...

twitter

श्री नरेंद्र मोदी

स्टार्टअप इंडिया आंदोलन नए भारत को दर्शाता है, यह हमारे युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और उद्यम द्वारा संचालित है। युवा स्टार्टअप उद्यमियों के बीच गतिशीलता उत्कृष्ट है।

.....

श्री अमित शाह

परिवर्तन का संकल्प लेकर सत्ता में आई ममता बनर्जी बंगाल को पतन की ओर ले गई। वोट बैंक की राजनीति के कारण ममता सरकार ने बंगाल को देश-विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनाकर रख दिया है।

.....

श्री राजनाथ सिंह

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्ववाली सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। नई फसल बीमा योजना केवल प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ 'सुरक्षा कवच' के रूप में कार्य नहीं करेगी बल्कि किसानों के हितों की रक्षा भी करेगी। इस नई योजना में न केवल पूर्व की योजनाओं की खामियों को दूर किया गया है, बल्कि प्रीमियम को काफी कम कर दिया गया है।

.....

श्रीमती स्मृति ईरानी

शोध यात्री कार्यक्रम के तहत छात्र, इतिहासकार, फोटोग्राफर श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वे जिन देशों में यात्रा करेंगे, वे वहां भारतीयों द्वारा की गई ऐतिहासिक यात्राओं को ढूढ़ेंगे। इन यात्राओं पर लिखी गई पुस्तक भी प्रकाशित की जाएगी।

.....

श्री नरेंद्र मोदी *@narendramodi*

पीएसएलवी सी31 के सफल प्रक्षेपण और आईआरएनएसएस-1ई को सटीकता के साथ कक्षा में स्थापित किए जाने के अवसर पर इसरो और हमारे वैज्ञानिकों को उनके उत्साह और दृढ़ संकल्प के लिए बधाई!

.....

श्री अमित शाह *@AmitShah*

सपा, बसपा और कांग्रेस ने गन्ना किसानों को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है। जहां-जहां भाजपा की सरकारें आई, वहां कृषि मजबूत हुयी है।

.....

श्री सुरेश प्रभु *@sureshpprabhu*

हम सभी परिचालनों में पूर्ण पारदर्शिता लागू करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं, गलत करने के लिए कोई जगह नहीं।

.....

पाथेय

संगठन

भारतीय जनता पार्टी एक मानवीय संगठन है। उसके पुर्जे धातु के बने हुए निर्जीव पुर्जे नहीं हैं। मनुष्य एक धातु का निर्जीव टुकड़ा नहीं है। वह एक सजीव विचारवान इकाई है। मानवीय संगठन निर्जीव धातु से बने हुए मशीन जैसे नहीं चलाया जा सकता। वह रोबोट नहीं है, वह कम्प्यूटर नहीं है, इन बातों को ध्यान में रखकर ही उसको चलाया जा सकता है।

समाज के सभी क्षेत्रों को और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता बनाने के लिए हमारा संगठन सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होना आवश्यक है। ऐसे सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठनात्मक आधार पर ही जो नीतियां बनेंगी, वही देश को एक रख सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी। हमारा दृष्टिकोण जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं।

- कुशाभाऊ ठाकरे

अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष बनने से संगठन को मिलेगी मजबूती

श्री अमित शाह सर्वसम्मति से पुनः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। एक ओर जब लोग उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी किस प्रकार अपने अध्यक्ष चुनती है, पार्टी की एकता एवं एकात्मता से भारतीय राजनीति की इतिहास में पुनः अपनी अमिट छाप छोड़ दिया। बहुत से लोगों को अचरज हुआ कि एक राजनैतिक दल में कैसे इतना जीवंत आंतरिक लोकतंत्र की संस्कृति विकसित कर सकता है जहां एकता एवं एकात्मता का पल-पल साक्षात्कार होता हो। राजनैतिक दल जहां झगड़े-टंटे के घर बन गये हों तथा समय-समय पर बंटते रहते हैं और यहां तक वंशवाद एवं परिवारवाद के शिकार हो जाते हैं, वहीं भाजपा ने विचारधारा एवं समर्पण के आधार पर एक अनूठा राजनैतिक आदर्श देश के सामने खड़ा किया है। जबकि एक ओर राजनैतिक दल आपसी कलह के शिकार नजर आते हैं दूसरी ओर भाजपा एकता एवं एकात्मता से ओत-प्रोत जीवंत आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

भाजपा का आंतरिक लोकतंत्र सांगठनिक चुनावों पर आधारित है जो जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक होता है। यह एक विराट कार्य है जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी होती है। अब जबकि भाजपा देश के कोने-कोने में पहुंच चुकी है तथा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, इसके सांगठनिक गतिविधियां और भी अधिक विशालकाय हो चुकी है। इतना विशाल कार्य इतनी सहजता से चलना ही इस बात का प्रमाण है कि भाजपा अपने आप में एक अनूठी पार्टी है। यह मां भारती की आराधना करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो निरंतर भारत के वैभव की साधना में लगी है। यह भाजपा कार्यकर्ताओं के निःस्वार्थ समर्पण का ही परिणाम है कि पद और सत्ता के लिए यहां कोई राग-द्वेष नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं के हृदय में सत्ता नहीं बल्कि मां भारती के वैभव का स्वप्न बसा हुआ है। हर बार जब सांगठनिक चुनाव होते हैं तब भाजपा कार्यकर्ताओं का यह संकल्प पुनः देखने को मिलता है।

पिछले 18 महीनों में श्री अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में संगठन को एक नई दिशा एवं गति दी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड एवं जम्मू-कश्मीर में मिली बड़ी जीत के साथ-साथ सदस्यता महाभियान एवं महासंपर्क अभियान के माध्यम से संगठन ने तीव्रता से अपने कदम बढ़ाये हैं। इन कार्यक्रमों के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण महाभियान भी चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली है तथा वैचारिक प्रतिबद्धता और भी अधिक दृढ़ हुई है। पार्टी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकती है जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और संगठन के शीर्ष के बीच तारतम्यता बनी रहे। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें राजनीति के विभिन्न पहलुओं से उभरते चुनौतियों का सामना करने में कार्यकर्ता सक्षम बने। एक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी संगठन की कल्पना के साथ श्री अमित शाह ने निरंतर प्रवास एवं बैठकों से सांगठनिक कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित किया है। उनके अथक प्रयासों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं तथा भाजपा न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गई है बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है।

आज भाजपा सरकार न केवल केन्द्र में है बल्कि इसे अनेक प्रदेशों में भी इसे जनता की सेवा का अवसर मिला है। यह समय है कि पार्टी सुशासन की नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जनाकांक्षाओं

को पूरा करने के लिए नई व्यवस्थाओं का साथ-साथ निर्माण करें। नये क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार के साथ-साथ श्री अमित शाह ने पार्टी में विभागों एवं प्रकल्पों की मूर्त-रूप दिया है। भाजपा अब बहुआयामी प्रगति तथा भविष्योन्मुखी योजना के साथ कार्य कर रही है। दूरदृष्टि के साथ लिए गये निर्णयों से पार्टी सुदृढ़, विकसित एवं समृद्ध भारत की कल्पना को साकार करने में तत्पर है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर पूरी दुनिया में बसे भारतीय आशा एवं विश्वास के साथ देख रहे हैं तथा उनके व्यापक दृष्टि की सराहना कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अमित शाह पार्टी को नये आयाम देने में जुटे हैं ताकि पार्टी पर जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसे पूरा किया जा सके।

उनका सर्वसम्मत पुनः निर्वाचित होने से संगठन की गति को न केवल बल मिला है बल्कि देशभर के कार्यकर्ताओं में नये उत्साह का संचार हुआ है। ■

नेताजी से जुड़ी 100 फाइलों की पहली किस्त अवर्गीकृत

नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलों की पहली किस्त को केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को अवर्गीकृत कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार जाकर इन डिजिटल फाइलों का शुभारंभ किया। वे नेताजी के परिजनों से भी मिले जिनमें प्रोफेसर चित्रा घोष, श्री चंद्र बोस और श्री सूर्य कुमार बोस शामिल थे।

भारत के प्रधानमंत्री ने 14 अक्टूबर 2015 को नेताजी के परिजनों से अपने आवास पर हुई मुलाकात में घोषणा की थी कि भारत सरकार नेताजी से जुड़ी फाइलों को क्रमबद्ध रूप में अवर्गीकृत करेगी और उन तक जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।

इस कड़ी में 33 फाइलों की पहली लाट को प्रधानमंत्री कार्यालय ने अवर्गीकृत किया था और उन्हें 4 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया गया था।

इसके बाद गृह मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय ने भी उनके पास उपलब्ध नेताजी से जुड़ी फाइलों को अवर्गीकृत करने की इस प्रक्रिया को शुरू किया और बाद में उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंप दिया गया।

इस तरह पहले कदम के रूप में राष्ट्रीय संग्रहालय ने प्राथमिक संरक्षण उपचार और डिजिटाइजेशन के बाद नेताजी से जुड़ी 100 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। बाकी फाइलें भी प्राथमिक संरक्षण उपचार और डिजिटाइजेशन के बाद सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

डिजिटल फाइलों को एक वेबसाइट पर डाला जाएगा जो खास तौर से एनआईसी द्वारा बनाई गई है। वेबसाइट का पता है - www.netajipapers.gov.in ■

अमित शाह दोबारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने

श्री शाह के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी : नरेन्द्र मोदी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 24 जनवरी को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में दूसरी बार सर्वसम्मति से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। श्री अमित शाह के नामांकन के समर्थन में संसदीय दल के प्रस्ताव सहित 20 राज्यों से 17 प्रस्ताव राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी, श्री अविनाश राय खन्ना जी को सौंपा गया। संसदीय दल के प्रस्ताव में प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री वेंकैया नायडू, श्री नितिन गडकरी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री मनोहर पार्रिकर, श्री अनंत कुमार, श्री जे.पी. नड्डा, श्री थावरचंद गहलोत, श्री रवि शंकर प्रसाद, श्री राधामोहन सिंह, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री पीयूष गोयल आदि कई वरिष्ठ मंत्रियों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन व्यक्त किया।

इसके अलावा राज्यों से आए प्रस्ताव में मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्रीमती वसुंधरा राजे, डॉ. रमन सिंह, श्री लक्ष्मीकांत पारसेकर, श्री देवेन्द्र फडणवीस, श्री मनोहर लाल खट्टर आदि प्रमुख नेताओं ने प्रस्तावक के रूप में अपना समर्थन किया। इस अवसर पर गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदी बेन पटेल, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास एवं विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक एवं वरिष्ठ नेतागण आदि उपस्थित होकर अपना समर्थन व्यक्त किया। गौरतलब है कि अध्यक्ष पद पर श्री शाह के कार्यकाल के दौरान पार्टी की सदस्यता में तेजी से वृद्धि दर्ज हुई और चार राज्यों में पार्टी सत्ता में आई।

श्री अमित शाह के फिर पार्टी अध्यक्ष चुने जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीटर पर लिखा-'श्री अमित शाह के भाजपा अध्यक्ष बनने पर बधाइयां। मैं आश्वस्त हूं कि उनके नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी।' केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि पार्टी शाह के नेतृत्व में जबर्दस्त प्रदर्शन करेगी। श्री सिंह ने कहा, सिर्फ एक नामांकन हुआ और वह अमित शाह का था। मेरा मानना है कि इसका कारण पार्टी सदस्यों का एकमत से हुआ निर्णय था। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी जबर्दस्त प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने भी शाह के दोबारा भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। श्री जेटली ने ट्वीट किया, भाजपा अध्यक्ष के तौर पर श्री अमित शाह के पुन: निर्वाचन पर बहुत-बहुत बधाई। नेतृत्व की इस जिम्मेदारी में सफलता के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।

केंद्रीय शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा

कि वह सबसे सक्षम व्यक्ति और अच्छे रणनीतिकार हैं। उनमें संगठनात्मक क्षमता है। उनके नेतृत्व में हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और मुझे यकीन है कि आने वाले सालों में पार्टी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा, वह हमारी विचारधारा को लेकर प्रतिबद्ध हैं और वह पार्टी का संदेश देश के कोने-कोने तक ले जाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं।

श्री अमित शाह के फिर पार्टी अध्यक्ष चुने जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीटर पर लिखा-'श्री अमित शाह के भाजपा अध्यक्ष बनने पर बधाइयां। मैं आश्वस्त हूं कि उनके नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी।' केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि पार्टी शाह के नेतृत्व में जबर्दस्त प्रदर्शन करेगी। श्री सिंह ने कहा, सिर्फ एक नामांकन हुआ और वह अमित शाह का था। मेरा मानना है कि इसका कारण पार्टी सदस्यों का एकमत से हुआ निर्णय था। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी जबर्दस्त प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने भी शाह के दोबारा भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। श्री जेटली ने ट्वीट किया, भाजपा अध्यक्ष के तौर पर श्री अमित शाह के पुनः निर्वाचन पर बहुत-बहुत बधाई। नेतृत्व की इस जिम्मेदारी में सफलता के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।

केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, वह बहुत बड़े आयोजक हैं और पार्टी के सामाजिक विस्तार के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। चाहे लोक सभा चुनाव हो या विधान सभा चुनाव या पंचायत चुनाव, शाह ने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया है ताकि चुनावी मुकाबलों में पार्टी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उनमें दृढ़ता और जुनून है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुश हैं और हमारे दिलोदिमाग में उम्मीद है कि पार्टी उनके नेतृत्व में सफलता की नई उंचाइयां छुएगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कहा, एक बार फिर भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर अमित शाह जी को हार्दिक बधाई। अमित जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल के कारण महाराष्ट्र और भाजपा को काफी फायदा हुआ है और काफी कामयाब पल देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे यकीन है कि उनके जीवंत नेतृत्व में पार्टी का आधार और बढ़ेगा और इसका झंडा देश के कोने-कोने में फहराएगा। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष श्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि पार्टी शाह के नेतृत्व में नई उंचाइयां छुएगी।

श्री शाह के दोबारा भाजपा अध्यक्ष चुने जाने का स्वागत करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री और असम के वरिष्ठ पार्टी नेता श्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि शाह के नेतृत्व में पार्टी आने वाले असम विधानसभा चुनावों में इतिहास रचेगी और राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। श्री सोनोवाल ने कहा, अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा असम में जीत हासिल करने जा रही है। राज्य में कांग्रेस को मात देकर पार्टी इतिहास रचेगी।

एक ट्वीट कर श्री अमित शाह ने उनमें भरोसा दिखाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं, संसदीय बोर्ड और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। श्री शाह ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से आपकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। पार्टी को नई उंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आपके मार्गदर्शन और समर्थन को लेकर उत्सुक हूं।

चेन्नई में डीएमडीके प्रमुख श्री विजयकांत ने शाह को दोबारा भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि उनके कार्यकाल में पार्टी के सपने साकार होंगे। डीएमडीके के संस्थापक अध्यक्ष श्री विजयकांत ने कहा, मुझे यकीन है कि आपकी स्पष्ट सोच, आपका प्रभाव और आपकी कड़ी मेहनत भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सपना साकार करने में मददगार होगी।

बाद में एक ट्वीट कर श्री अमित शाह ने उनमें भरोसा दिखाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं, संसदीय बोर्ड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। श्री शाह ने कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से आपकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। पार्टी को नई उंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आपके मार्गदर्शन और समर्थन को लेकर उत्सुक हूं। ■

अप्रतिम संगठनात्मक क्षमता और सामरिक योजना के जनक अमित शाह

अप्रतिम संगठनात्मक क्षमता और सामरिक योजना के लिए प्रसिद्ध श्री अमित शाह, जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता हैं, जिनका एक प्रतिष्ठित राजनीतिक रिकार्ड है और वे आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने-जाते हैं।

श्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में मुंबई के एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ था। सोलह वर्ष की आयु तक वह अपने पैतृक गांव मान्सा, गुजरात में रहे और वहीं स्कूली शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उनका परिवार अहमदाबाद चला गया। बालपन में वह सदैव महान राष्ट्रभक्तों की जीवनियों से प्रेरित हुआ करते थे, इसी प्रेरणा के फलस्वरूप उन्होंने भी मातृभूमि की सेवा करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का स्वप्न देखा।

श्री अमित शाह के परिवार में पहले कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं था, इसके बजाय, उनके परिवार में मानव प्रेम की वो भावना थी जिसने श्री अमित शाह के अंदर समाज की सेवा करने की इच्छा को जगाया। 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में, श्री अमित शाह एक तरुण स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संपर्क में आए। इसी निर्णय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। श्री शाह ने संघ की विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए चार वर्ष तक कार्य किया।

अभूतपूर्व चुनावी उपलब्धियां

1995 में श्री अमित शाह पहली बार सरखेज विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रुप में चुने गए। वह 1998 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित किए गए। इस बार उन्होंने यह सीट 1.30 लाख मतों के अंतर से जीती। वर्ष 2002 में विधानसभा चुनावों से पूर्व श्री अमित शाह को 'गौरव यात्रा' का सह-संयोजक बनाया गया। जिसके बाद श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सत्ता में आई। इस बार भी श्री अमित शाह ने सरखेज से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। इस बार जीत का अंतर बढ़ कर 1,58,036 हो गया। श्री अमित शाह को गृह, परिवहन और निषेध जैसे अहम मंत्रालयों का दायित्व सौंपा गया तथा गुजरात के गृह मंत्री के रूप में उनके काम को बहुत सराहा गया। समय के साथ-साथ उनकी लोकप्रियता और लोगों से जुड़ाव बढ़ता गया। वर्ष 2007 में सरखेज विधानसभा क्षेत्र ने एक बार फिर श्री अमित शाह को विजयश्री का माला पहनाया और इस बार वह 2,32,832 मतों के भारी अंतर से जीते। वह राज्य कैबिनेट पर लौटे तथा उन्हें गृह, परिवहन, निषेध, संसदीय मामले, कानून और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया।

वर्ष 2007 में श्री नरेन्द्र मोदी और श्री अमित शाह गुजरात स्टेट क्रिकेट ऐसोसिएशन के क्रमशः चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन बने तथा कांग्रेस के 16 साल के प्रभुत्व को समाप्त किया। इस अवधि में श्री अमित शाह अहमदाबाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट के चेयरमैन भी रहे।

2010 का वर्ष अभूतपूर्व चुनौतियों का वर्ष था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने श्री अमित शाह पर फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगाया तथा उन्हें कैद कर लिया गया। बाद में, उनके निरपराध होने का सत्यापन गुजरात हाई कोर्ट ने किया कि ''अमित शाह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई

मामला नहीं बनता। इस कांग्रेसी षड्यंत्र का भी वही अंजाम हुआ जो श्री अमित शाह के साथ चुनावी मुकाबले में हुआ था। उन्हें 90 दिनों के भीतर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और प्रतिशोध की राजनीति बुरी तरह परास्त हुई। 2015 विशेष सीबीआई अदालत ने भी श्री अमित शाह को सभी आरोपों से इस रिमार्क के साथ मुक्त कर दिया कि यह केस 'राजनीति' से प्रेरित था।

श्री अमित शाह की चुनावी विजय अटूट बनी रही। 2012 में उन्होंने नव

निर्मित नारायणपुर विधानसभा से अपनी लगातार पांचवी विजय हासिल की। इस बार वह 60,000 से अधिक वोटों से जीते जबकि परिसीमन के कारण कुल मतों की संख्या पहले के मुकाबले महज एक चौथाई रह गई थी। पार्टी ने उनकी चुनावी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें 2013 में भाजपा का महासचिव बनाया। 2014 में होने वाले बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। उनकी लंबी और परिश्रम से भरपूर राजनीतिक यात्रा में यह बहुत ऊंचा पड़ाव था। अपनी विधानसभा जीत के पश्चात् श्री अमित शाह के पास उत्सव के लिए समय बहुत कम था क्योंकि आम चुनावों में भाजपा को संपूर्ण विजय दिलाने हेतु नेतृत्व का महाकाय दायित्व उनके सामने था। चुनावी गणित के महारथी श्री अमित शाह को छोटे से छोटे आंकड़े पर गौर करने के लिए जाना जाता है और इसीलिए वह जानते थे कि केन्द्र में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जीतना बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने अगला साल उत्तर प्रदेश के हर कोने में यात्रा करते हुए बिताया, पार्टी कार्यकर्ताओं को अभिप्रेरित किया, उन्हें नई ऊर्जा दी तथा भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता के साथ पार्टी के विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाया।

इसका नतीजा शानदार रहा और उत्तर प्रदेश में भाजपा व उसके सहयोगियों ने 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश से मिले इस व्यापक जनसमर्थन के बल पर भाजपा ने अकेले अपने दम पर ही लोकसभा में 272 के आंकड़े को पार करके बहुमत हासिल किया।

भाजपा ने श्री अमित शाह के समर्पण, परिश्रम और संगठनात्मक क्षमताओं को सम्मानित कर उन्हें 2014 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। ज्यादा शक्तियों के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां आती हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री अमित शाह ने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने तथा पार्टी के सदस्यता आधार के विस्तार के लिए देश के हर राज्य का दौरा किया। उनके इस अभियान के परिणाम चकित करने वाले रहे। 11 करोड़ सदस्यों के साथ उन्होंने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया। भाजपा को सशक्त करने के अपने संकल्प को उन्होंने यहीं विराम नहीं दिया, बल्कि पार्टी की विचारधारा के प्रसार एवं जन संपर्क बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से कार्यक्रम प्रारंभ किए। इनमें से एक कार्यक्रम था 'महासंपर्क अभियान' जिसका लक्ष्य नए बने सदस्यों को पार्टी की मुख्यधारा में लाकर उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय करना था।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व एवं श्री अमित शाह की सुविचारित चुनावी रणनीतियों का ही यह परिणाम था कि बतौर पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह के कार्यकाल में भाजपा ने छह में से चार विधानसभा चुनावों में विजय प्राप्त की। महाराष्ट्र, झारखंड व हरियाणा में पार्टी के मुख्यमंत्री बने तथा जम्मू और कश्मीर में उप-मुख्यमन्त्री के पद के साथ भाजपा गठबंधन सरकार का हिस्सा बनी।

बीते अट्ठारह महीनों में भारतीय जनता पार्टी को इन उपलब्धियों तक पहुंचाने में श्री शाह के अथक प्रयास किया और इन्होंने इस अवधि में रोजाना औसतन 495 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा की। इस दौरान श्री अमित शाह ने पूरे देश में 2,65,600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। ■

कैबिनेट ने नई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को मंजूरी दे दी, जो किसानों के कल्याण के लिए लीक से हटकर एक अहम योजना है।

किसान हितैषी सरकार का नया तोहफा

13 जनवरी को लोहिड़ी, पोंगल एवं बीहू जैसे त्यौहारों के शुभ अवसर पर किसान हितैषी सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया। यह योजना खरीफ 2016 से लागू होगी। किसानों के लिए बीमा योजनाएं समय-समय पर बनती रहीं हैं, किंतु इसके बावजूद अब तक कुल कवरेज 23 प्रतिशत हो सका है।

सभी योजनाओं की समीक्षा कर अच्छे फीचर शामिल कर किसान हित में और नए फीचर्स जोड़कर फसल बीमा योजना बनाई गई है। इस प्रकार यह योजना पुरानी किसी भी योजना से किसान हित में बेहतर है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत)
1	खरीफ	2.0 प्रतिशत
2	रबी	1.5 प्रतिशत
3	वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें	5 प्रतिशत

वर्ष 2010 से प्रभावी मोडीफाइड एनएआईएस में प्रीमियम अधिक हो जाने की दशा में एक कैप निर्धारित रहती थी जिससे कि सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी, परिणामत: किसान को मिलने वाली दावा राशि भी अनुपातिक रूप से कम हो जाती थी।

उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में धान की फसल के लिए 22 प्रतिशत वास्तविक प्रीमियम था। किसान को 30 हजार रुपए के कुल बीमा पर कैप के कारण मात्र 900 रुपए और सरकार को 2400 रुपए प्रीमियम देना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान के हित में सरकार का योगदान

छोटा प्रीमियम - बड़ा बीमा	
छोटा प्रीमियम	
कम प्रीमियम	· प्रीमियम में किसान के योगदान की अधिकतम सीमा निर्धारित - **अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर** (केवल नाम मात्र भार): o खरीफ - 2 प्रतिशत o रबी - 1.5 प्रतिशत · शेष भार सरकार द्वारा वहन · **अतः औसतन किसान के योगदान पर सरकार की अनुमानित 5 गुनी भागीदारी**
एक फसल - एक दर	· पहले की जिलावार अलग-अलग दर के बजाय, अब **देश भर** में हर फसल की **एक समान दर**
बड़ा बीमा	
सही मुआवजा	· फसल के **पूर्ण मूल्य का बीमा** - मुआवजे में न कमी न कटौती
ज्यादा जोखिम - ज्यादा सहायता	· अधिक प्रीमियम होने पर बीमा की राशि सीमित करने की पहले की नीति समाप्त · ज्यादा जोखिम में फंसे किसानों की खास सहायता का स्पष्ट निर्णय
ज्यादा सुरक्षा	· संरक्षित आपदाओं के दायरे को बढ़ाया गया - **जल भराव, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान** जैसी आपदाओं का सम्मिलन

अधिक व्यापक	· अनेक योजनाओं के होने के बावजूद ज्यादा किसान बीमा सुरक्षा से वंचित रहे। · वर्तमान के 23% कवरेज को अगले 2-3 वर्षों में 2 गुना करके **50%** तक ले जाने का लक्ष्य · **ऋण न लेने वाले किसानो** पर खास ध्यान
किसान अनुकूलता	
स्थानीय आकलन	· क्षेत्र-आधरित नुकसान के आकलन से **खेत-आधरित नुकसान आकलन** की तरफ कदम · **ओले, भूस्खलन, जलभराव** और फसल कटाई के बाद **चक्रवात एवं बेमौसम बारिश** जैसी आपदाओं से नुकसान का खेत-स्तर पर आकलन
शीघ्र भुगतान	· मोबाइल, सेटेलाइट जैसी **टेक्नालॉजी** के व्यापक उपयोग से **सही आकलन** और **शीघ्र भुगतान** · **निश्चित समय-सीमा** में दावा निपटान
सरलीकरण	· पुरानी स्कीमों का नयी स्कीम में सम्मिलन - पुरानी स्कीमों की अच्छाइयों का समावेश और खामियों का निवारण · **अनेक स्कीमों, अनेक नियमों** के जटिल जाल से आजादी
एक देश एक योजना	· देश भर में एक समान नियमों और शर्तों की **समान योजना**

पड़ता था। किंतु शत-प्रतिशत नुकसान की दशा में भी किसान को मात्र 15 हजार रुपए की दावा राशि प्राप्त होती।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार कुल बीमा पर 22 प्रतिशत वास्तविक प्रीमियम आने पर किसान मात्र 600 रुपए प्रीमियम देगा और सरकार 6000 हजार रुपए का प्रीमियम देगी। शत-प्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को 30 हजार रुपए की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी। अर्थात् उदाहरण के प्रकरण में किसान के लिए प्रीमियम 900 रुपए से कम होकर 600 रुपए। दावा राशि 15000 रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए।

बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल है उसे दावा राशि मिल सकेगी। ओला, जलभराव और भूमि स्खलन जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सरकार की ओर से एक सौगात : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कैबिनेट द्वारा मंजूर किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर के जरिये किसानों के लिए सन्देश भेजा जिसके प्रमुख निम्न अंश हैं:

- 'किसान बहनों-भाइयों आप सब जब लोहड़ी, पोंगल, बिहु जैसे अलग-अलग त्योहार मना रहे हैं, तब सरकार की ओर से एक भेंट-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'
- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब तक जितनी योजनाएं थीं उनकी विशेषताओं को तो समाहित करती ही है लेकिन जो कमियां थी उनका प्रभावी समाधान देती है'
- 'अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर, सरल टेक्नालॉजी जैसे मोबाइल फोन का उपयोग कर नुकसान का त्वरित आंकलन, निश्चित समय सीमा में पूरे दावे का भुगतान'
- 'किसान बहनों-भाइयों और भी कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ना सरल है, लाभ लेना सुगम है। आप जरूर जुड़िए'
- 'यह एक ऐतिहासिक दिन है, मेरा विश्वास है किसानों के कल्याण से प्रेरित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी'
- आपदाओं के दायरे को बढ़ाया गया - जल भराव, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान जैसी आपदाओं को सम्मिलित किया'

किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम : अमित शाह

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले तीन दशक से चलाई जा रहीं अलग-अलग फसल बीमा योजनाएं केवल 23 फीसद किसानों तक ही पहुंच पाई है जबकि मोदी सरकार ने अगले 3 वर्षों में देश के अधिक-से-अधिक किसानों को इस बीमा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

किसान हितैषी मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा स्वतंत्र भारत का एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा सुरक्षित फसल, समृद्ध किसान की अवधारणा को अमलीजामा पहनाने की दिशा में मोदी सरकार द्वारा किया गया एक सार्थक और व्यापक प्रयास है।

मोदी सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इनश्योरेन्स स्कीम से कई गुना बेहतर है। देशभर के लगभग 14 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। ■

पुरानी योजनाओं के अंतर्गत यदि किसान के खेत में जल भराव (पानी में डूब) हो जाता तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस पर निर्भर करती कि यूनिट आफ इंश्योरेंस (गांव या गांवों के समूह) में कुल नुकसान कितना है। इस कारण कई बार नदी नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी।

इसमें फसल कटने के बाद का भी नुकसान शामिल किया गया है। फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी।

योजना में टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे की फसल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके।

रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जाएगी। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन के माध्यम से अप-लोड कराए जाएंगे।■

नौजवानों को सबसे बड़ी सौगात 'स्टार्टअप इंडिया'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जनवरी को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्टार्टअप इंडिया की कार्य योजना को औपचारिक रूप से जारी किया। अब यह अभियान मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया अभियानों की शृंखला से जुड़ गया है। स्टार्टअप योजना से नये उद्यमियों को अपना उद्यम प्रारम्भ करने में आसानी होगी। दरअसल, सरकार लायसेंस परमिट राज खत्म करके व्यवसाय प्रारम्भ करना आसान बनाना चाहती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जनवरी को नई दिल्ली में स्टार्ट-अप इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के शुभारंभ से पहले उद्यमशीलता के विभिन्न पहलुओं पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्चुअल प्रदर्शनी का भ्रमण किया और स्टार्ट-अप उद्यमियों से संवाद किया।

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले 10 शानदार स्टार्ट-अप इनोवेटर्स ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 15 अगस्त को स्टार्ट-अप इंडिया अभियान लॉन्च किया था, तो इस घोषणा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग इसे समर्थन दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आम तौर पर सफल स्टार्टअप उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जो खास विचारों पर काम करते हैं या लोगों के सामने आ रही समस्याओं को हल निकालने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पैसा कमाना उनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं, लेकिन अक्सर उनके उप-उत्पाद होते हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इनोवेटर्स अक्सर दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना से आगे बढ़ते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं, भारत के युवा नौकरी खोजने वाले के बजाय रोजगार पैदा करने वाले बनें। उन्होंने कहा कि यदि एक स्टार्टअप सिर्फ 5 लोगों को भी रोजगार दे, तो यह भी राष्ट्र की बड़ी सेवा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि युवा इनोवेटर्स को फसल हानि और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने 10 हजार करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड आफ फंड बनाने का ऐलान करते हुए बताया कि इस फंड में चार साल तक हर साल 2500 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्टार्टअप योजना से स्टैंडअप योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार चाहती है प्रारंभ किए गए नये उद्यम अपने पैरों पर भी खड़े होने में सक्षम हों, इसके लिए उनकी सरकार पूरा प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को पहले तीन साल तक लाभ पर आयकर के भुगतान से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्टार्टअप के लिए एक सरल निकासी नीति पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की फास्ट-ट्रैकिंग पर काम कर रही है।

उन्होंने स्टार्टअप कारोबारों के लिए पेटेंट शुल्क में 80 फीसदी तक छूट की घोषणा की और कहा कि स्टार्टअप के लिए 9 श्रम और पर्यावरण कानूनों के वास्ते एक स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही अटल इनोवेशन मिशन पेश किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली

➡

स्टार्टअप इंडिया की मुख्य बातें

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नया उद्यम शुरू करने वाले स्टार्टअप कारोबारियों के लिए 16 जनवरी 2016 को तीन साल का टैक्स अवकाश, पूंजीगत लाभ टैक्स से छूट, इंस्पेक्टर राज मुक्त परिवेश और वित्तपोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने सहित कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणा की।
- श्री मोदी ने 9 श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए स्व:प्रमाणन योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उद्यम शुरू होने के पहले तीन साल के दौरान कोई जांच नहीं की जाएगी।
- देश में नवप्रवर्तन सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित इन नये उद्यमों के लिये एक उदार पेटेंट व्यवस्था भी लाई जाएगी। पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- स्टार्टअप उद्यमियों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने उन्हें बढ़ावा देने के वास्ते एक कार्य योजना की घोषणा की। इन उद्यमों को देश में संपत्ति और रोजगार सृजन करने वाले अहम क्षेत्र के तौर पर देखा जा रहा है।
- दुनियाभर में स्टार्टअप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है। सरकार इन उद्यमों को सरकारी खरीद ठेके लेने के मामले में भी मानदंड में कई तरह की छूट देगी। स्टार्टअप उद्यमों को सरकारी ठेकों में अनुभव और कारोबार सीमा के मामले में छूट दी जायेगी।
- श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफे पर व्यवसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी। ऐसे उद्यमों में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20 प्रतिशत की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ टैक्स से भी छूट होगी। यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूंजीकोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होगी।
- प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिवाला कानून में स्टार्टअप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जायेगा। इसके तहत 90 दिन की अवधि में ही स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे।
- स्टार्टअप के लिए 19 बिंदुओं की कार्ययोजना पेश करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूंजीगत लाभ टैक्स में छूट से स्टार्टअप भी एमएसएमई के बराबर आ जाएंगे।
- स्टार्टअप में टैक्स छूट उचित बाजार मूल्य के ऊपर निवेश पर दी जाएगी। इनकम टैक्स कानून के तहत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से उपर मिलने वाले वित्तपोषण पर प्राप्तकर्ता को कर देना होता है।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व:प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर नियामकीय बोझ कम होगा। स्व:प्रमाणन अनुपालन की यह व्यवस्था कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान, ठेका कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि कोष, पानी और वायु प्रदूषण कानूनों के मामले में उपलब्ध होगी।
- सरकार का स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम देश में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके और देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकें।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और नियामकीय संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिये एक एप और पोर्टल जारी किया जाएगा।
- पेटेंट आवेदनों को कम लागत पर परीक्षण के लिये कानूनी समर्थन भी दिया जायेगा। इससे स्टार्ट अप को भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामले में जागरूकता आएगी और वह अपने आईपीआर की सुरक्षा और उनका व्यवसायीकरण भी कर सकेंगे।
- स्टार्टअप के मामले में सरकारी खरीद के नियमों में ढील दिये जाने से स्टार्ट अप को भी दूसरे अनुभवी उद्यमियों और कंपनियों के बराबर का मंच उपलब्ध हो जायेगा।
- स्टार्टअप को वित्तपोषण का समर्थन देने के लिये सरकार 2,500 करोड़ रुपये का शुरुआती कोष बनाएगी जिसमें अगले 4 साल के दौरान कुल 10,000 करोड़ रुपये का कोष होगा।
- इस कोष का प्रबंधन निजी क्षेत्र के पेशेवर करेंगे जबकि जीवन बीमा निगम इस कोष में सह-निवेशक होगा। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए बनाए गये ऋण गारंटी कोष से बैंकिंग प्रणाली से भी स्टार्टअप के लिये उद्यम ऋण का प्रवाह होगा। इस कोष से जोखिम के बदले गारंटी उपलब्ध हो सकेगी।
- सरकार की ओर से एक राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अगले चार साल तक सालाना 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया जाएगा। ■

ने स्टार्ट अप इंडिया अभियान के उद्घाटन भाषण में कहा कि स्टार्टअप मूवमेंट के तहत जमीनी स्तर पर उद्यमों और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने पर जोर दिए जाने की बात कही। श्री जेटली ने कहा कि सरकार अगले महीने बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी, जिससे देश में स्टार्ट अप स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। ■

भाजपा के भविष्य से देश का भविष्य जुड़ गया है

– अटल बिहारी वाजपेयी

29-30 नवंबर, 1 दिसंबर 1996 को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश भाजपा अभ्यास वर्ग में दिए गए उद्‌बोधन के संपादित अंश हम यहां सुधी पाठकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है दूसरा भाग-

भय एवं आतंक का खात्मा भी जरूरी

हम सभी जानते हैं कि पिछड़े हुओं में भी कुछ अधिक पिछड़े हैं और कुछ कम पिछड़े हुए हैं। दलित समाज का एक अलग वर्ग है। परिगणित जाति के लोगों का स्थान सबसे नीचे की श्रेणी में आता है। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि दलित वर्ग परम्परागत जाति और वर्ण की व्यवस्था से उतना त्रस्त नहीं है जितना भय और आतंक से परेशान है। गांव में इसके पास जमीन है और लाठी भी है। वह इन दोनों के बल पर पिछड़े वर्ग का होते हुए भी अपने से अधिक पिछड़े वर्ग का शोषण करता है। उसे डराता धमकाता है, संख्या के बल पर वह वर्ग सत्ता में भी आना चाहता है। कहीं आने में सफल भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच चुनाव समझौता न होने का यही रहस्य है। दोनों दलों ने संयुक्त सरकार बनाई थी किन्तु मिलकर काम करने के बजाए वह टूटकर अलग हो गये। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। यह उत्पीड़न अधिकतर सपा के समर्थकों की ओर से होता था। उनके पास लाठी और जमीन पहले से भी थी और अब सत्ता भी हाथ में आ गई है। बसपा ने सपा ने नाता तोड़ लिया। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार का समर्थन किया था। प्रारम्भ में वह सरकार ठीक चली किन्तु बाद में पटरी से उतर गई उसने संकीर्ण जातिवाद को जगाकर समाज

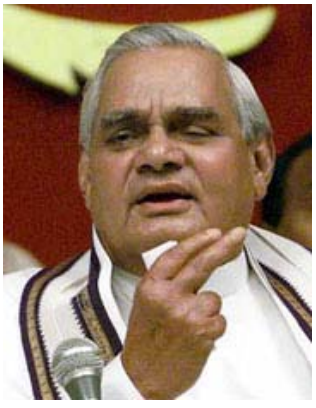

को छिन्न-छिन्न करने का प्रयास किया। शासन तंत्र में भी पृथकता की भावना भर गई। बसपा की सरकार को बाहर से समर्थन देने का हमारा उद्‌देश्य केवल मुलायम सिंह सरकार के आतंक से प्रदेश को केवल मुक्ति दिलाना ही नहीं, समाज में समरसता को प्रोत्साहित करना भी था। दलित हिन्दू समाज का अभिन्न अंग है। उन्हें शोषण से मुक्त करके समाज में सम्मान ओर उपयुक्त स्थान दिलाना एक सामाजिक आदर्श की पूर्ति करना है। किन्तु बसपा नेताओं की विचारधारा सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित नहीं करती है, समाज को बदलने की बात करती, भले ही बदलने की प्रक्रिया में समाज के और भी टुकड़े हो जायें। इसके विपरीत हम समाज में सुधार चाहते हैं, जिससे समाज बदले भी और उसकी एकता कायम रहे। इस काम में हमें दलितों का भी समर्थन मिल रहा है। इसे और बढ़ाना है। इस दलित समाज को केवल एक वोट बैंक नहीं मानते, हम उसे समाज का अभिन्न और अटूट अंग मानते हैं और इसी आधार पर उसके साथ बराबरी और भाईचारे का बर्ताव करने में विश्वास करते हैं।

हमारी एक चिंतन एवं विचारधारा है

भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों में अपना प्रभाव और अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल हुई है। इसके पीछे एक चिन्तन है, एक विचारधारा है। मैं अभी-अभी परिसर में पं. दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण कर के आया हूं। वह महान चिंतक और कुशल संगठनकर्ता थे। उनकी विशेषता पुराने चिन्तन को देश और काल के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित करने में थी। समय के साथ समस्याओं का रूप बदलता है, नयी समस्याएं खड़ी होती हैं, कुछ पुरानी समस्याएं नये स्वरूप में आती हैं। उन समस्याओं को अलग करने के लिये मूलभूत चिन्तन के आधार पर नयी व्याख्याएं और नयी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। हम एक आदर्श राज्य की स्थापना चाहते हैं। इसलिये प्रारम्भ में धर्मराज्य की बात कही, बाद में अयोध्या आन्दोलन के प्रकाश में हमने रामराज्य की स्थापना को अपने लक्ष्य के रूप में लोगों के सामने रखा। धर्मराज्य और रामराज्य में कोई अन्तर नहीं है। दोनों में लक्षण समान हैं किन्तु कभी-कभी समय में परिवर्तन के साथ कोई शब्दावली अधिक आकर्षक हो जाती है।

जब जनसंघ का निर्माण हुआ तो विश्व साम्यवाद और पूंजीवाद में बंटा हुआ था। भारतीय चिन्तन ने दोनों को अस्वीकार किया था। हम राज्य शक्ति

और आर्थिक शक्ति का एकत्रीकरण नहीं चाहते, न कुछ व्यक्तियों के हाथों में और न राज्य के ही हाथों में। हम विकेन्द्रित व्यवस्था के हामी हैं। साम्यवाद शोषण से मुक्ति और राज्य के तिरोहित होने की बात करना है किन्तु व्यवहार में वह केन्द्रीकरण का पुरस्कर्ता बनकर खड़ा हो जाता है। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की विफलता सुनिश्चित जानकर उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का प्रतिपादन किया, जिसमें पूंजीवाद की तरह न तो समस्याओं को टुकड़ों में देखा जाता है और न व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसके पुरुषार्थ पर पानी फेर कर एक अधिनायकवादी व्यवस्था का ही प्रतिपादन किया जाता है। आज विश्व में नाटकीय परिवर्तन हो रहे हैं विचारों के जगत में इतनी उथल-पुथल हुई है जिसकी कुछ वर्ष पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी साम्यवाद का दावा था कि वह एक दिन सारे संसार को लाल रंग में रंग देगा। आज वह स्वय इतना बदरंग हो गया है कि उसे पहचानना भी मुश्किल है साम्यवाद पर खड़ा सोवियत संघ बिखर गया, सोवियत साम्राज्य का पतन हो गया। अब सर्वहारा वर्ग की सरकार बनाने की बात कोई नहीं करता। यहां तक कि कोई मार्क्स की बात भी नहीं करता, लेनिन का भी कोई उल्लेख नहीं करता। इन विचारकों का मत था कि पश्चिमी औद्योगीकरण के कारण अमीर और अमीर होते जायेंगे और गरीब अधिक गरीब होते जायेंगे दोनों के बीच की खाई बढ़ेगी। संघर्ष में मजदूर सफल हो जायेंगे, उनकी सरकार बन जायेगी। सारे संसार में साम्यवाद स्थापित हो जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

साम्यवाद परास्त

साम्यवाद का जीवन दर्शन भौतिकता पर आधारित होने के कारण परास्त हो गया। इसमें मात्र अर्थ का ही विचार किया गया था, किन्तु अर्थ का विचार भी सम्पूर्ण नहीं था। सोवियत रूस की जनता ने जब टेलीविजन पर अमेरिका के बाजारों की तस्वीरें देखी और वहां की समृद्धि के दृश्य देखे, उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं से भरे एक से एक बढ़कर सुपरबाजार देखे तो उनका मानस डोल गया, विश्वास डिग गया। वे सोचने लगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि चढ़ाकर वह जिस प्रगति की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, उस प्रगति की तुलना में पूंजीवादी देश उन्हें पीछे छोड़कर मीलों आगे दौड़ गये हैं। उनके मन में भी प्रश्न उठने लगे हैं कि ऐसी व्यवस्था का क्या लाभ है? साम्यवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण किया था, पूरा ढांचा अधिनायकवादी था। न राजनैतिक स्वतत्रंता थी, न प्रेस की आजादी। राज्य में आतंक पर आधारित एक व्यवस्था थी। रात में पुलिस किसी भी व्यक्ति का दरवाजा खटखटाकर उसे पकड़कर रख सकती थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। वह व्यक्ति लापता हो सकता था। जीवन भर श्रम करने के लिए साइबेरिया भेजा जा सकता था। किसी अदालत में उसकी सुनवाई नहीं थी, कोई वकील उसके पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं था। आज हम मानव अधिकारों की चर्चा बड़े जोर-शोर से करते हैं। समाजवादी देशों में मानवाधिकारों का कोई स्थान नहीं था। लाखों लोग साइबेरिया में निर्वासित कर दिये गये। लाखों भूखे मरने के लिये विवश कर दिये गये हैं। यह सब एक नई सभ्यता और नया समाज बनाने के नाम पर हुआ। न वह नई सभ्यता आई और न वह नया समाज बना। साम्यवादी नेताओं का सपना टूट गया, उन्होंने भविष्य का जो चित्र खींचा था, वह बिखर गया। कम्युनिस्टों ने अपनी पराजय मान ली, न वह आर्थिक प्रगति ला सकें और न नैतिकता तथा आध्यात्मिकता, जिस पर किसी व्यवस्था का निर्माण ही कर सके।

आज क्यूबा को छोड़कर कोई देश साम्यवाद की बात नहीं करता है चीन के नेता जो इन दिनों भारत आये हुए हैं, बड़े कट्टरपथी कम्युनिस्ट समझे जाते थे। वे भी आजकल बाजारी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अपनी समर्थकों को बहकाने और अपने मन को समझाने के लिये वह मार्केट के साथ सोशलिस्ट शब्द जरूर लगा रहे हैं, किन्तु इससे किसी का समाधान नहीं होगा। उन्मुक्त अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट कैसे हो सकती है? जो सोशलिस्ट है, उसे उन्मुक्त के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है सोशलिस्ट राज्य में नियंत्रण अनिवार्य है और यदि बाजारी अर्थव्यवस्था है तो उसका खुला होना निश्चित है। बाजार अपनी गतिविधि आप तय करेगा, वह किसी के नियंत्रण में नहीं चलेगा। क्यूबा को भी अपनी रीति-नीति में परिवर्तन करना पड़ रहा है कम्युनिज्म का कोई नामलेवा और पानी देवा नहीं है।

हां, भारत में जरूर कम्युनिस्ट पार्टियां उपयुक्त अवसर जानकर अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास में लगी हैं। संयुक्त पार्टी की जो सरकारें बनी हैं, इसमें कम्युनिस्ट संख्या में कम होते हुए भी अपना रौब गालिब करने की कोशिश में लगे हैं। वह कम्युनिज्म की बात नहीं करते, न्यूनतम कार्यक्रम का नारा लगाते हैं। पश्चिम बंगाल और केरल तक सीमित उनका संगठन वैचारिक भ्रांति का शिकार होकर क्षीण होता जा रहा है। जब विचारधारा के नाते साम्यवाद से हमारी टक्कर नहीं है, उस एकांगी दर्शन की पराजय निश्चित थी।

क्रमशः

सिक्किम के पूर्व राज्यपाल वी रामाराव का निधन

सिक्किम के पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री वी रामाराव का 17 जनवरी को हैदराबाद में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे।

श्री रामाराव ने 2002 से 2015 तक सिक्किम के राज्यपाल के रूप में काम किया, उनके परिवार में उनकी पत्नी वसंता कुमारी और पुत्र श्रीनिवास शामिल हैं। मृदु भाषी स्वच्छ राजनीतिज्ञ के रूप में 60 वर्षों तक कार्य करते रहे। उन्होंने 1956 में सदस्य के रूप में जनसंघ में शामिल हुए और वे भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रूप में कार्य करते रहे, जब तक कि इसका स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदल नहीं दिया गया। उन्होंने 1993 से 2001 तक निरन्तर दो अवधि में राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में काम किया और वे 2002 से 2007 के बीच पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे।

श्री रामाराव का जन्म 12 दिसम्बर 1935 में कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम में हुआ और वे 1966, 1972, 1978 और 1984 में निरन्तर चार बार हैदराबाद ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वे अन्तिम अवधि में कौंसिल के पार्टी के लोर नेता रहे। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के सीनेट के रूप में भी काम किया।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का शोक संदेश

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री वी रामा राव के असमय निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री शाह ने अपने शोक संदेश में कहा, ''श्री राव का जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित था। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से हुई और वे अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे।

श्री राव का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं भगवान से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को सामर्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।''

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी का शोक संदेश

मुझे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ है। श्री रामाराव भाजपा के वरिष्ठ नेता भी थे।

वे आंध्रप्रदेश में जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के लिए 1966 से निरन्तर चार अवधियों के लिए हैदराबाद ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वे पक्के आदर्शों के व्यक्ति थे। उन्होंने सार्वजनिक व राजनीतिक दोनों मुद्दों पर बहस में भाग लिया।

उनके भाषणों में हास्य और विट से भरी होती थीं और प्रायः तनावपूर्ण क्षणों को हलका कर दिया करती थी।

मैं श्री रामाराव के परिवार को अपनी हार्दिक संवेदना प्रगट करता हूं। प्रभु, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

पं. दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि (11 फरवरी) पर विशेष

कुशल संगठक एवं विचारक राजनेता

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चन्द्रभान ग्राम में 25 सितम्बर, 1916 को सुप्रसिद्ध ज्योतिषी पं. हरीराम उपाध्याय के पौत्र पं. भगवती प्रसाद की पत्नी श्रीमती राम प्यारी ने प्रातः सूर्य की प्रथम किरण के साथ जिस बालक को जन्म दिया, वही बड़ा होकर पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना गया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को ब्रज के मथुरा जिले के छोटे से गांव जिसका नाम "नगला चंद्रभान" था, में हुआ था। पं. दीनदयाल उपाध्याय का बचपन घनी परेशानियों के बीच बीता। दीनदयाल के पिता का नाम 'भगवती प्रसाद उपाध्याय' था। इनकी माता का नाम 'रामप्यारी' था जो धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। दीनदयाल जी के पिता रेलवे में काम करते थे लेकिन जब बालक दीनदयाल सिर्फ तीन साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और जब तक उन्होंने सातवां वसंत देखा तब तक उन पर से मां का भी साया हट चुका था। 7 वर्ष की कोमल अवस्था में दीनदयाल माता-पिता के प्यार से वंचित हो गए थे। दीनदयाल ने किसी तरह से पढ़ाई पूरी की उसके बाद उन्होंने नौकरी न करने का निश्चय किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करना शुरू कर दिया। संघ के लिए काम करते-करते वह खुद इसका एक हिस्सा बन गए और राष्ट्रीय एकता के मिशन पर निकल चले।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की एक और बात उन्हें सबसे अलग करती है और वह थी उनकी सादगी भरी जीवनशैली। इतना बड़ा नेता होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी अहंकार नहीं था।

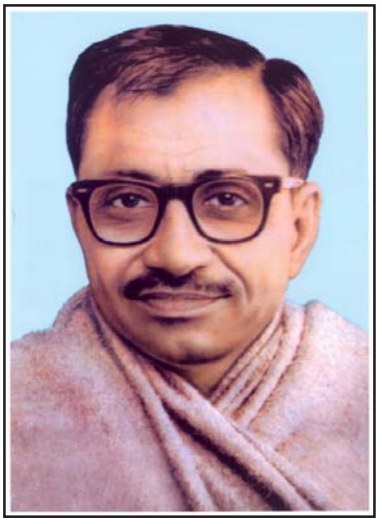

भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन पर श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एकात्म मानववाद में साम्यवाद और पूंजीवाद, दोनों की समालोचना की गई है। एकात्म मानववाद में मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरुप राजनीतिक कार्रवाई हेतु एक वैकल्पिक सन्दर्भ दिया गया है।

उपाध्यायजी नितांत सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी सादगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने धोती तथा कुर्ते में और अपने सिर पर टोपी लगाकर सरकार द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा दी जबकि दूसरे उम्मीदवार पश्चिमी सूट पहने हुए थे।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन पर श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एकात्म मानववाद में साम्यवाद और पूंजीवाद, दोनों की समालोचना की गई है। एकात्म मानववाद में मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरुप राजनीतिक कार्रवाई हेतु एक वैकल्पिक सन्दर्भ दिया गया है।

11 फरवरी, 1968 को पं. दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मुगलसराय रेलवे यार्ड में उनकी लाश मिलने से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। अपने प्रिय नेता के खोने के बाद भारतीय जगसंघ के कार्यकार्ता और नेता आनाथ हो गए थे। पार्टी को इस शोक से उबरने में बहुत समय लगा।

उनकी इस तरह हुई हत्या को कई लोगों ने भारत के सबसे बुरे कांडों में से एक माना। पर सच तो यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज के लिए सदैव अमर हैं। ■

पश्चिम बंगाल में इतिहास रचेगी भाजपा : कैलाश विजयवर्गीय

मध्य प्रदेश से आने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। आप पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा का प्रभारी रहते हुए वहां के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के लिए सफल प्रचार अभियान चलाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है।

कमल सन्देश सम्पादकीय मंडल के सदस्य राम प्रसाद त्रिपाठी द्वारा किए गए एक ताजा साक्षात्कार में श्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों और योजनाओं पर बात की और यह विश्वास जताया कि भाजपा कड़ी टक्कर देते हुए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार को राज्य की सत्ता से हटाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान और उसके बाद भी हमारा ध्यान मुख्यत: राज्य के विकास पर होगा। बातचीत के मुख्य अंश:

– पूरी संभावना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आगामी अप्रैल या मई महीने में होंगे। ऐसे में, आप राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को कैसे देखते हैं? आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति के विषय में आपका क्या कहना है?

यह धारणा प्रबल हो रही है कि ममता बनर्जी नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात कतई ठीक नहीं हैं। वर्तमान सरकार राज्य के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण और सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक अशांति के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों की जनसांख्यिकीय स्थिति ही पूरी तरह से बदल गई है।

दूसरी चीज कि राज्य सरकार नकली नोट निर्माताओं, अफीम उत्पादकों और ड्रग माफियाओं को भी सुरक्षा प्रदान की है। माफिया राज राज्य के तमाम जिलों में फैलता जा रहा है। परिणामत: इन क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोग अत्यंत भय में जीने को विवश हैं। मुझे लगता है कि ये स्थितियां न केवल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए अत्यंत अनुकूल हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक भी हैं।

तीसरी बात कि तृणमूल कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति से राज्य के बहुसंख्य लोग नाखुश हैं। अत: हमारा मुख्य उद्देश्य गुंडा/माफिया राज का खात्मा कर राज्य में लोकतंत्र और कानून के शासन की स्थापना करना है।

– हाल ही में राज्य में मालदा जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ऐसी घटनाओं को रोकने की बजाय राज्य सरकार दंगाइयों को बचाने में लगी है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है और क्या उसे आगामी विधानसभा चुनावों में इसका लाभ मिलेगा?

जनवरी के पहले सप्ताह में अचानक मालदा हिंसा भड़क उठी। उन्मादी भीड़ ने पुलिस थानों को क्षति पहुंचाई, दर्जनों वाहनों को जला दिया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित तक कर दिया। हिन्दु जो उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हैं, के घरों को आग के हवाले कर उन्हें वह इलाका छोड़कर जाने को विवश किया गया। इस घटना के बाद वे हिन्दू परिवार अब तक वापस नहीं लौटे हैं। स्पष्ट होता है कि यह एक पूर्व-नियोजित वारदात है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार की भी इसमें सहभागिता रही है। अगर सरकार इसमें शामिल नहीं हैं तो फिर उसने

भाजपा के प्रतिनिधमंडल को दो-दो बार मालदा जाने से क्यों रोका और एक कट्टरपंथी धार्मिक संगठन को राज्य में दो लाख से अधिक लोगों की सभा करने की अनुमति क्यों दी?

- **वह कौन-से प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें भाजपा चुनाव के दौरान उठाएगी? क्या पार्टी के पास पश्चिम बंगाल के चुनावों के लिए कोई विशेष एजेंडा भी है?**

बंगाल में भाजपा का केवल एक एजेंडा है- विकास। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार राज्य के विकास के मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम रही है, जिसके चलते बंगाल में बेरोजगारी संकट और पलायन चिंताजनक तरीके से बढ़े हैं। विगत चार वर्षों में 500 औद्योगिक इकाईयां बंद हो चुकी हैं। चाय बगान घटते जा रहे हैं और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कोई पहल नहीं हो रही। अत: हम बंगाल के लोगों के पास मोदीजी के विकास के एजेंडे के साथ जाएंगे। हमारी सरकार राज्य में निवेश के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करेगी, जिससे रोजगार पैदा होगा और राज्य को तेजी से विकासपथ पर अग्रसर होगा। इसके अलावा महिला सुरक्षा, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने तथा राज्य में कानून का शासन स्थापित करने पर भी हमारा मुख्य ध्यान होगा।

- **विगत चार वर्षों के दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सारदा चिट-फण्ड आदि कई बड़े घोटाले किए हैं तो क्या आप आगामी चुनावों के दौरान इन बड़े घोटालों को मुद्दा बनाएंगे?**

विगत चार वर्षों के दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केवल दो ही प्रमुख काम किए हैं, वो काम हैं बड़े-बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार तथा तुष्टिकरण की राजनीति। सारदा चिट-फण्ड जैसे कुछ बड़े घोटाले सामने आ गए तो सरकार ने तमाम और घोटालों को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अभी तो चिट-फण्ड घोटाले से सम्बंधित बहुत सारी नई बातें सामने आनी शेष हैं। गांवों के गरीब लोग इन घोटाले के प्रमुख पीड़ित हैं, इसलिए भाजपा निश्चित ही इन घोटालों का मुद्दा उठाएगी, जिससे तृणमूल कांग्रेस सरकार का सच सामने आ सके। हम एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह सभी तथ्य मतदाताओं के सामने रखेंगे और इस सरकार के भाग्य का फैसला जनता पर छोड़ देंगे। साथ ही, भाजपा मोदीजी की केंद्र सरकार की ही तरह राज्य में भी भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त सरकार देने का वादा करेगी।

- **विगत वर्ष बिहार चुनावों में सामजिक समीकरणों ने बड़ी भूमिका अदा की तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों में भी सामाजिक समीकरण कोई भूमिका अदा कर सकते हैं? या लोग विकास के एजेंडे पर मतदान करेंगे?**

विगत वर्ष बिहार चुनावों में सामाजिक समीकरणों की निश्चित ही बड़ी भूमिका रही लेकिन, पश्चिम बंगाल में लोग सचेत और विकासोन्मुख हैं। राज्य के विगत विधानसभा चुनावों में उन्होंने दशकों पुराने कम्युनिस्ट शासन का अंत कर ममता बनर्जी को विकास, शांतिपूर्ण माहौल और प्रगतिशील राज्य की एक उम्मीद के साथ मौका दिया था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सरकार के शासन में आज वे अपने भविष्य के प्रति निराश और भ्रमित होकर जीने को मजबूर हैं।

वर्तमान में लोग राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण, भ्रष्टाचारमुक्त शासन और राज्य का विकास चाहते हैं। भाजपा बंगाल, बंगाली संस्कृति, परंपरा और बंगाली लोगों, सबको बचाएगी। हम मौजूदा सरकार को हटाने और राज्य में लोगों के लिए विकास लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए लोग निश्चित ही हमें एक मौका देंगे।

- **पश्चिम बंगाल का प्रभारी रहते हुए आपने राज्य के विभिन्न इलाकों में व्यापक रूप से भ्रमण किया है तो क्या आपको लगता है कि पार्टी राज्य में शासन की बागडोर हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है?**

श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से बंगाल में भाजपा की लोकप्रियता में कई गुणा वृद्धि हुई है। पिछले डेढ़ सालों में राज्य में हमारी पार्टी से एक धारा की तरह नए लोग जुड़े है। हमारे कार्यकर्ता भी राज्य के प्रत्येक हिस्से में में पार्टी को मजबूती देने के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। एक और बात कि मौजूदा सरकार ने दिखने लायक कोई विकास का काम नहीं किया है। इसलिए वो बहुत तेजी से मतदाताओं का भरोसा खोती जा रही है। वहीं, भाजपा का संगठन राज्य में मजबूत हुआ है। पश्चिम बंगाल की टीम चुनाव में टक्कर देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे और इतिहास रचेंगे। ■

मालदा हिंसा

भाजपा ने की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

गत 3 जनवरी 2016 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में 2 लाख से ज्यादा की संख्या में लोगों की एक गैर-कानूनी भीड़ का एकत्रीकरण हुआ। इदारा-ए-शरिया द्वारा इस भीड़ को सुनियोजित तरीके से एकत्रित करके स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक भवनों पर हमला किया गया। न तो इस गैर-कानूनी सभा के आयोजन के बारे में राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही इस गैर कानूनी सभा में उपस्थित लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं आज जनता को भयभीत किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई की गई है।

भारतीय जनता पार्टी का तीन सदस्यीय संसदीय दल 11 जनवरी 2016 को मालदा पहुंचा। उन्होंने स्थानीय जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक से आग्रह भी किया कि कम से कम शान्ति समिति के सदस्यों से मिलने का अवसर दिया जाए, जिससे जनसामान्य के मन में जो अविश्वास का माहौल बना है, उसे कम करके विश्वास की बहाली की जा सकें। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन पर दबाव डालकर न केवल तथ्यों को छुपाने का, अपितु सबूतों को सुनियोजित तरीके से समाप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

मालदा हिंसा पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुई हिंसा के मामले में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने 16 जनवरी को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से भेंट की और उन्हें दो ज्ञापन भी सौंपे। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी महासचिव कैलाश विजय वर्गीय, सचिव श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह एवं श्री राहुल सिन्हा और अन्य नेता शामिल थे। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति से भेंट करके उनसे इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया। भाजपा का मानना है कि ममता बनर्जी की राज्य सरकार घटना को काबू करने में नाकाम रही है। भाजपा का यह भी मानना है कि ऐसी घटनाएं देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हैं।

गौरतलब है कि इस माह की शुरुआत में हुई इस हिंसा में लाखों की भीड़ ने स्थानीय पुलिस स्टेशन को जला दिया था। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ममता बैनर्जी सरकार से 3 जनवरी को मालदा के कलियाचक में हुई हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। पार्टी ने अपने सांसदों की एक टीम, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव, श्री एस. एस. अहलूवालिया एवं श्री बी.डी. राम शामिल हैं, भी कलियाचक भेजी थी, लेकिन उसे वहां जाने से रोक दिया गया था। ■

वाराणसी

प्रधानमंत्री ने वितरित किए जरूरत के कई सामान व सहायक उपकरण
महामना एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी को वाराणसी में आयोजित एक सामाजिक आधिकारिता शिविर में शिरकत की और जरूरत के कई तरह के सामान व सहायक उपकरण वितरित किए।

वितरित किए जाने वाले जरूरत के सामान में सिलाई मशीन, ब्रेल किट, हियरिंग एड और अन्य कई तरह के स्मार्ट उपकरण शामिल थे। लाभार्थियों में दिव्यांग और विधवाएं शामिल थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उस भाषण को याद किया जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से भी पहले दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार गरीबों और निचले तबके के लोगों की सेवा के प्रति समर्पित रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि वाराणसी में लगा ये कैंप देश भर में लगे उन 1800 कैंपों में से एक है जो कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से लगाए हैं। ये संख्या पिछली सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कैंप लगाने से जरूरी सामान व सहायक उपकरणों के वितरण की गतिविधियों में बिचौलिए खत्म हो गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन पर निजी हमले हो रहे हैं, क्योंकि बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है और शासन व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले उन्हें उनके गरीबों और कमजोर तबकों की सेवा के मार्ग से विचलित नहीं कर पाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन पर निजी हमले हो रहे हैं, क्योंकि बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है और शासन व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले उन्हें उनके गरीबों और कमजोर तबकों की सेवा के मार्ग से विचलित नहीं कर पाएंगे।

प्रधानमंत्री ने रोजमर्रा में 'विकलांग' की जगह 'दिव्यांग' शब्द के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फोकस उनकी विकलांगता पर नहीं बल्कि उनमें मौजूद उन असाधारण क्षमताओं पर होगा जिनसे वह धन्य हैं।

प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के दिव्यागों को आसानी से सुलभ कराने वाले सुगम्य भारत अभियान के बारे में भी बात की।

उन्होंने आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त महामना एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसकी शुरुआत के लिए रेलवे को बधाई भी दी।

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे लोगों की बस के हादसे का शिकार हो जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मंत्री और अधिकारी फौरन अस्पताल की ओर रवाना हुए और घायलों की अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। उन्होंने उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्हें मामूली चोटें आई थीं और जो हादसे के बावजदू कार्यक्रम में आए थे।■

ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक

'अन्त्योदय' और 'सामाजिक सद्भाव' हैं पार्टी के सिद्धांत और संविधान : अमित शाह

गत 10 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सरकार की योजनाओं और संविधान प्रदत्त अधिकारों को पिछड़े समुदायों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विगत वर्ष हमने कई उपलब्धियां हासिल कीं। इस दौरान न केवल हमारी सदस्य संख्या 11 करोड़ से अधिक हो गई, बल्कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव भी हासिल किया। लेकिन अब हमें अपने संगठन की संरचना पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हम निरंतर रूप से समाज के पिछड़े, शोषित और वंचित समुदायों के लिए कर सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओबीसी मोर्चा राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, इसका उद्देश्य अपने आप में अत्यंत व्यापक और जनकल्याण से सम्बंधित है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारों को पिछड़े समुदायों के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना ओबीसी मोर्चा का लक्ष्य होना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित अन्त्योदय की अवधारणा पार्टी की समस्त गतिविधियों के मूल में उपस्थित रहती है। उन्होंने कहा कि 'अन्त्योदय' और 'सामाजिक सद्भाव' ही पार्टी के संविधान और सिद्धांत हैं। इतिहास प्रमाण है कि जब भी राज्य या केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, हमने सदैव पिछड़े, शोषित और वंचित समुदाय के लोगों की आर्थिक उन्नति और सामजिक कल्याण के लिए काम किया है तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाए और कार्यक्रम चलाए हैं।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि हमारे काम मुख्यत: सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी द्वेष या कड़वाहट के हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि संविधान के दिशा-निर्देशों के तहत शोषित और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम किया जाय। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें मंच दें तथा समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दायित्व प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संचालित अधिकांश योजनाएं गरीब और वंचित समुदायों के कल्याण को समर्पित हैं। मोदी सरकार ने गरीबों, जिनके पास आजादी के 68 साल बाद भी एक बैंक खाता तक नहीं था, के लिए बैंकों के दरवाजे खोलते हुए अब तक 19 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए हैं।

श्री शाह ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से विकासपथ पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत और भारतीयों का सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है। अब यह भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो ओबीसी मोर्चा के माध्यम से सरकार द्वारा समाज के पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं तथा पार्टी के विचारों और मूल्यों से समाज के अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति को अवगत कराए। ओबीसी मोर्चा को पिछड़े समुदायों और सरकार के बीच एक सेतु की तरह काम करना चाहिए। ■

भाजपा प्रदेश अध्यक्षों का निर्वाचन

महाराष्ट्र

रावसाहेब पाटिल दोबारा चुने गये भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

मराठवाड़ा की जालना लोकसभा सीट से सांसद श्री रावसाहेब दानवे पाटिल 18 जनवरी को महाराष्ट्र भाजपा के दोबारा प्रदेशाध्यक्ष चुने गये। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिसका राजस्व मंत्री श्री एकनाथ खडसे ने अनुमोदन किया।

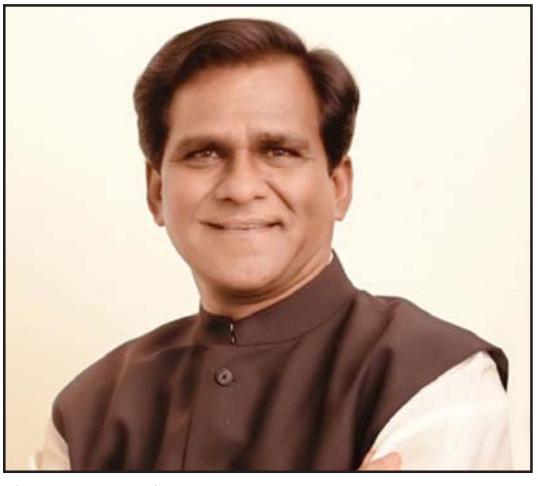

सांसद श्री पाटिल के दोबारा निर्विरोध प्रदेशाध्यक्ष चुने जाने के वक्त पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम रुपाला केंद्रीय निरीक्षक के रूप में और प्रदेश की प्रभारी सुश्री सरोज पांडे व चुनाव अधिकारी के रूप में श्री सुजितसिंह ठाकुर उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री फडणवीस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पाटिल ने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सरकार के जनहित के कार्य जनता तक पहुंचाने का काम सफलतापूर्वक किया है। उनके नेतृत्व में भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छी सफलता पाई है। जिसकी वजह से उन्हें दोबारा प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है।

श्री पाटिल ने दोबारा प्रदेशाध्यक्ष बनाये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, प्रदेश की प्रभारी सुश्री सरोज पांडे, सह प्रभारी श्री राकेश सिंह और मुख्यमंत्री श्री फडणवीस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति और महानगरपालिका के चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाना उनका लक्ष्य रहेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वे केंद्र व राज्य सरकार के कामों को गांव-गांव तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ■

ओडिशा

बसंत पांडा ओडिशा के नए भाजपा अध्यक्ष

भाजपा नेता व विधायक श्री बसंत पांडा 14 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी, ओडिशा प्रदेश के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भाजपा के चुनाव अधिकारी श्री राजकिशोर दास ने कहा कि राज्य विधानसभा के सदस्य श्री पांडा को राज्य में पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति ने इस पद के लिए पर्चा नहीं भरा था।

नुआपाड़ा से विधायक पांडा (54) ने श्री कनक वर्धन सिंहदेव की जगह ली। श्री पांडा ने कहा, 'पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते राज्य में पार्टी को मजबूत करने और बीते 15 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल द्धबीजदऋ की भ्रष्ट सत्ता से लड़ने के लिए मैं सबका सहयोग लूंगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कल्याण कार्यक्रमों को राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। श्री पांडा दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। साल 2000 और साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। ■

संस्कारहीन राजनीति देश के लिए घातक

– इंजी. अरुण कुमार जैन

हिन्दुस्तान की वर्तमान राजनीति में कुछ दल एवं राजनेता जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं एवं आचरण कर रहे हैं उससे लगता है कि उनमें या तो राजनीतिक संस्कारों की कमी होती जा रही है या राजनीतिक संस्कार हैं ही नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के व्यक्तिगत बुलावे पर उनके पैतृक गांव पहुंचे तो भारत में कांग्रेस सहित कई दलों के पेट

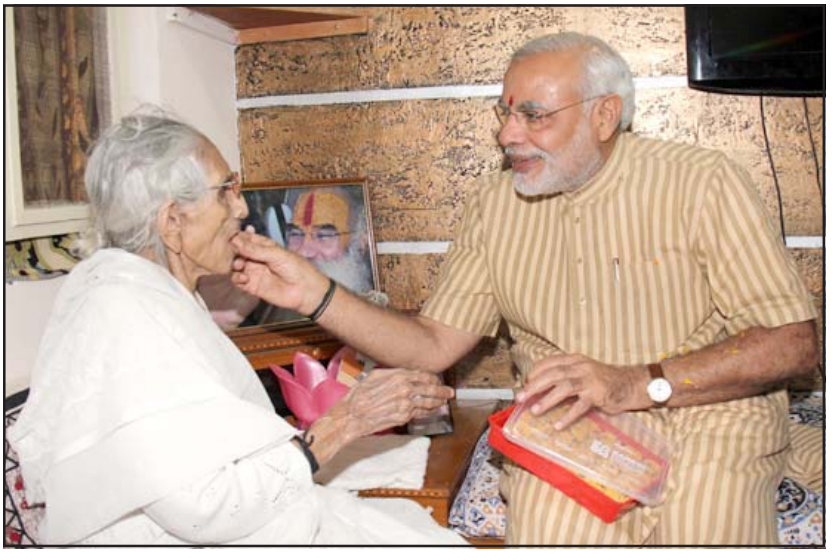

में मरोड़ होने लगा।

विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे की निंदा करनी शुरू कर दी है। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा पहले से था तो कोई कह रहा है कि श्री नरेद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी तो अब उसमें ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया। जो दल कदम-कदम पर सेकुलर होने का ढोंग करते हैं वे किसी भी सूरत में यह नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री एवं भाजपा मुस्लिम देशों एवं मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हों। ऐसे दल चाहते है कि धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदारी उन्हीं के पास रहे जिससे वे सांप्रदायिकता के कठघरे में भाजपा एवं श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को खड़ा करने का बहाना ढूंढ़ते रहें। प्रधानमंत्री एवं उनकी सरकार यदि एकदम सही दिशा में जा रही है तो पाखंडी किस्म के सेकुलर लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है।

सेकुलर दिखने के लिए कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग देशद्रोहियों एवं आतंकवादियों के पक्ष में भी वकालत करने लगते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सउदी अरब सहित दुनिया के तमाम देशों में प्रधानमंत्री एवं भारत की लोकप्रियता बढ़ रही है तो तथाकथित सेकुलर बिरादरी सारे राजनीतिक लोक-लाज एवं मर्यादा को भुलाकर सिर्फ निंदा करने में जुट गयी है। इस देश में तमाम ऐसे दल हैं जिनमें संस्कार तो हैं किंतु वे संस्कार जातिवाद, क्षेत्रवाद, अधिनायकवाद, परिवारवाद एवं तुच्छ राजनीतिक स्वार्थवाद से प्रेरित हैं। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद एवं संघवाद की बात करती है तो संस्कारहीन दलों एवं राजनेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है।

इसके विपरीत यदि प्रधानमंत्री की बात की जाये तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचकर श्री नवाज शरीफ की मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी नातिन को आशीर्वाद भी दिया। इसे कहते हैं संस्कार। राजधानी दिल्ली की सरकार एवं उसके प्रतिनिधि आजकल अपने कुसंस्कारों के लिए पूरी दुनिया में कुप्रचारित हो रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई छापा पड़ते ही मुख्यमंत्री महोदय इतना बौखला गये कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मनोरोगी एवं कायर करार दिया, इससे पूरे देश को पता चला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितने संस्कारी हैं? बात सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है उनके एक मंत्री कपिल मिश्रा ने तो प्रधानमंत्री को निठल्ला करार दिया।

इस प्रकार आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी एवं उनके नेताओं में कितना संस्कार है? यदि प्रधानमंत्री की बात की जाये तो वे प्रधानमंत्री बनने के बाद और भी विनम्र हो गये हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री बार-बार

प्रधानमंत्री का नाम इसलिए लेते रहते हैं कि प्रधानमंत्री भी उनका नाम बार-बार लें जिससे उनका कद भी प्रधानमंत्री के समकक्ष हो जाये। किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व एवं संस्कारित हैं कि बेमतलब की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। जहां तक दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं उनके सहयोगियों की बात है तो वे सत्ता पाने के बाद 'ठूंठा पेड़' की तरह अकड़ गये हैं जिसमें न तो छाया है और न ही फल। जबकि प्रधानमंत्री फलदार वृक्ष की तरह और भी झुक गये हैं यह सब सिर्फ अपने-अपने संस्कारों की वजह से है।

दिल्ली के स्वघोषित ईमानदार मुख्यमंत्री ईमानदार नेता अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले का आरोप लगाकर अपनी संस्कारहीन राजनीति का परिचय देते हैं तो 'नेशनल हेराल्ड' मामले में कुछ बोलने के नाम पर सांप सूंघ जाता है। दिल्ली की सत्ता संभाले साल भर नहीं हुआ किंतु अभी से जिस प्रकार दिल्ली सरकार के विभागों, विधायकों एवं मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए हैं। ऐसे में लगता है कि पांच साल पूरे होते-होते दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए अब तक के सभी रिकार्डों को ध्वस्त कर देगी।

दिल्ली के स्वघोषित ईमानदार मुख्यमंत्री ईमानदार नेता अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले का आरोप लगाकर अपनी संस्कारहीन राजनीति का परिचय देते हैं तो 'नेशनल हेराल्ड' मामले में कुछ बोलने के नाम पर सांप सूंघ जाता है। दिल्ली की सत्ता संभाले साल भर नहीं हुआ किंतु अभी से जिस प्रकार दिल्ली सरकार के विभागों, विधायकों एवं मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए हैं। ऐसे में लगता है कि पांच साल पूरे होते-होते दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए अब तक के सभी रिकार्डों को ध्वस्त कर देगी।

वीआईपी संस्कृति, सरकारी सुख-सुविधाओं से दूर रहने का दावा करने वाले अपनी सुख-सुविधाओं एवं वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर इतने उत्साहित, लालायित एवं उतावले हैं जैसे उनकी जन्मों-जन्मों की मुराद पूरी हो गयी और ऐसे लोगों को लगता है कि अन्ना हजारे के साथ उन्होंने जो आंदोलन किया था, उसका पूरा मुआवजा वसूल लिया है और पूरी जिदगी भर के लिए अपने को सुरक्षित कर लिया है।

आखिर यह सब क्या है? राजनीति में कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करता है उससे यह जाहिर होता है कि उसके संस्कार कैसे हैं? संस्कार अनेक रूपों में परिलक्षित होते हैं, चाहे वे बदजुबानी को लेकर हों, क्षेत्रवाद को लेकर हों, परिवारवाद के रूप में हों, अधिनायकवाद के रूप में हो या फिर किसी अन्य रूप में।

आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 'कहां मूंछ का बाल और कहां पूंछ का बाल' यानी कि राजनीतिक संरकारों एवं कार्यप्रणाली के मामले में इन लोगों से प्रधानमंत्री की कोई तुलना नहीं की जा सकती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी एवं पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्म दिन की बधाई दी तो यह उनके संस्कार ही हैं। स्व. नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा तो इसमें स्व. नरसिंह राव के राजनीतिक संस्कारों की झलक दिखती है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरह भारत का पक्ष रखा उससे पूरी दुनिया दंग रह गयी जबकि वे सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के नेता थे। इसे कहते हैं राजनीतिक संस्कार एवं दरियादिली।

जहां तक कांग्रेस पार्टी के संस्कारों की बात है तो निश्चित रूप से उसमें राजनीतिक संस्कार थे किंतु इस समय कांग्रेस का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है वे या तो बंद कमरों की राजनीति करते हैं या फिर श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल की चमचागिरी में कुछ भी ऊल-जुलूल बकते रहते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि किस प्रकार की भाषा बोलने से श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी प्रसन्न होंगे। उन्हें इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि यह वही कांग्रेस है जिसे राजनीतिक संस्कारों एवं मर्यादाओं की फिक्र रहती थी। इसी कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर आक्रमण करने से पहले देश के प्रमुख नेताओं, चाहे वे

सजा पक्ष के रहे हों या फिर विपक्ष के, भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के प्रमुख देशों में भेजा था, इसी कूटनीति के चलते पाकिस्तान का विभाजन संभव हो सका था। श्रीमती गांधी के इस कदम की तारीफ तत्कालीन विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जमकर की थी। इसे कहते हैं राजनीतिक संस्कार।

अभी हाल ही में संसद भवन में राजनीतिक संस्कार का एक अनूठा उदाहरण तब देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आप' के सांसद भगवत मान को बेचैन होने पर पानी का गिलास पकड़ाया जबकि भगवत मान उस समय प्रधानमंत्री के ही खिलाफ नारे लगा रहे थे।

वैसे भी इस देश की सदियों से गंगा-यमुनी संस्कृति रही है भारत भूमि ऋषियों, मुनियों, त्यागियों तपस्वियों, दानवीरों एवं शूरवीरों की रही है। समय-समय पर भांति-भांति के संस्कार देखने-सुनने को मिलते रहे हैं।

अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया एवं छिछोरगिरी की राजनीति के जिस हद तक पहुंचे उससे पता चलता है कि उनमें किस स्तर के राजनीतिक संस्कार हैं। राजनीतिक रूप से संस्कारों की बात की जाये तो पूरी दुनिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु वर्तमान में कुछ लोग अपने इस गौरवमयी इतिहास को कलंकित करने का काम कर रहे हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली ने ठीक ही कहा है कि आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक बहस का स्तर एकदम निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है। स्वराज अभियान के नेता श्री योगेंद्र यादव का भी मानना है कि आम आदमी पार्टी ने राजनीति का स्तर एकदम गिरा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता हों या लालू यादव या फिर अन्य तमाम लोग जो निम्न स्तर की राजनीति करने पर आमादा हैं, उनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 'अधजल गगरी छलकत जाय'। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा का तौर-तरीका कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी थप्पड़ खाने के लिए उसकी तरफ कर दो या फिर एक थप्पड़ का जवाब दो थप्पड़ मार कर दो, किंतु यदि आम जनभावना की बात की जाये तो वह महात्मा गांधी जी के ही तौर-तरीकों को आज भी पसंद करती है।

वर्तमान हालातों में देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी के ही रास्ते पर चल रहे हैं जबकि सच्चाई तो यह है कि उनके छप्पन इंच सीने की पूरी दुनिया में गूंज है। आतंकवादियों एवं अराजकतावादियों में उनके नाम की दहशत है यानी यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री में क्षमाशीलता एवं विनम्रता का गुण कूट-कूट कर भरा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति में 'क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को सीख' वाली कहावत को खूब चरितार्थ किया है। संस्कारहीन राजनीति के कारण आज देश में बुद्धिजीवियों का माने जाने वाले उच्च सदन राज्यसभा के औचित्य पर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे हैं।

गौरतलब है कि राज्यसभा इसलिए महत्वपूर्ण थी कि जो काम लोकसभा से छूट जाये, वह राज्यसभा अपने से पूरा कर दे। राज्यसभा इस बात के लिए नहीं थी कि उसे अखाड़े के रूप में तब्दील कर दिया जाये। आज राजनीति में जिस प्रकार का आचरण देखने को मिल रहा है। आखिर उससे देश का युवा वर्ग क्या सीख लेगा? सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाने, दूसरो की कमियां गिनाने एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने से किसका भला होगा?

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संस्कारहीन राजनीति देश के लिए सर्व दृष्टि से घातक है देश में राजनीति का स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा, अन्यथा आने वाला समय समस्याओं के समाधान का है न कि समस्यायें गिनाने का। इसलिए अभी से सभी राजनीतिक दलों, नेताओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, अन्यथा ये पब्लिक है- सब कुछ जानती एवं समझती है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री हैं)

संस्कारहीन राजनीति देश के लिए सर्व दृष्टि से घातक है देश में राजनीति का सार ऊंचा उठे, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा, अन्यथा आने वाला समय समस्याओं के समाधान का है न कि समस्यायें गिनाने का। इसलिए अभी से सभी राजनीतिक दलों, नेताओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सतर्क होने की जरूरत है अन्यथा ये पब्लिक है सब कुछ जानती एवं समझती है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट

2016–17 में चीन के मुकाबले करीब एक प्रतिशत अधिक होगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर

भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान आकर्षक बना रहेगा और 2016-17 के दौरान उसकी आर्थिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह वृद्धि दर चीन की वृद्धि के मुकाबले करीब एक प्रतिशत अधिक होगी। विश्व बैंक ने यह बात कही है।

विश्व बैंक ने अपनी ताजा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा है -विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर को वर्ष 2015 के लिये मामूली 0.2 प्रतिशत और 2016 तथा 2017 दोनों के लिये 0.1 प्रतिशत कम किया है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट हर छह माह में जारी की जाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान आकर्षक बना रहेगा क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में और गिरावट की आशंका है।

भारत समूचे एशिया क्षेत्र की प्रभावशाली अर्थव्यवस्था है और इसके इस साल में 7.8 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। अगले दो साल के दौरान इसके 7.9 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है।

विश्व बैंक का अनुमान है कि 2015 में चीन की अर्थव्यवस्था में 6.9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि रहने की उम्मीद है। इससे पहले विश्व बैंक ने जून में जो अनुमान लगाया था ताजा अनुमान उससे 0.3 प्रतिशत कम है।

रिपोर्ट के अनुसार चीन की आर्थिक वृद्धि वर्ष 2016 में 6.7 प्रतिशत और उसके बाद 2017 और 2018 दोनों साल में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार रूस और ब्राजील वर्ष 2016 में 0.3 प्रतिशत और 2017 में 0.4 प्रतिशत की संभावित वृद्धि के साथ लगातार मंदी के दौर में रहेंगे।

विश्व बैंक ने कहा है, ''दुनिया के अन्य विकासशील देशों के मुकाबले भारत में आर्थिक वृद्धि की दर लगातार बेहतर बनी रहेगी। निवेशकों की धारणा मजबूत बनी रहेगी और कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट के फलस्वरूप वास्तविक आय पर सकारात्मक असर पड़ने से इसको बल मिलेगा।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव के बावजूद पिछले वर्ष के दौरान भारतीय मुद्रा और शेयर बाजार ने अपनी बेहतर क्षमता का प्रदर्शन किया।

रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से मजबूत किया है और इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार सकारात्मक बना रहा।

इसमें कहा गया है कि भारत में जारी वित्तीय मजबूती के प्रयासों से केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के चार प्रतिशत के करीब आ चुका है जबकि वर्ष 2009 में यह 7.6 प्रतिशत की उंचाई पर था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में दक्षिण एशिया लगातार चमकता आकषर्क स्थान बना रहेगा। वर्ष 2016 में इसकी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत और कुछ ही दिन पहले समाप्त 2015 में सात प्रतिशत रहेगी।

इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र का चीन के साथ व्यापारिक लेन-देन दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले कम है और यह कच्चे तेल का विशुद्ध आयातक है इसलिये उसे वैश्विक बाजार में उर्जा के घटे दाम का लाभ मिलेगा।

पाकिस्तान (घटक लागत आधार पर) 4.5 प्रतिशत वृद्धि हासिल करेगा। ■

राज्यों से समाचार

कोकराझार (असम)

'राज्यों को केंद्र के हर पैसे का हिसाब देना होगा'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को कहा कि राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से मिलने वाले एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा। उन्हें खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का हिसाब रखना होगा। लोगों के धन की लूट को रोकना होगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जब उन्होंने विकास कोष को लेकर जवाबदेही मांगी तो असम सरकार और पूर्वोत्तर में कई अन्य राज्य सरकारें परेशान हो गईं। उन्होंने कहा, असम सरकार को हमें ब्योरा देना होगा कि विकास का धन कहां चला गया। पूर्वोत्तर में सभी सरकारों को पूरा हिसाब किताब देना होगा। इसी वजह से, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। वे मुझे पसंद करें या नहीं करें। मैं देश के लिए काम करता हूं। मैं विकास के लिए काम करता हूं।

केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का हवाला देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब से एनडीए सत्ता में आई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कई पहल की है। अब केंद्र सरकार का कम से कम एक मंत्री हर महीने पूर्वोत्तर का दौरा करता है। उन्होंने कहा, हमारे पास तीन सूत्री कार्यक्रम है-विकास, विकास और विकास। सभी समस्याओं का समाधान केवल विकास के जरिए ही किया जा सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार से भेजे जाने वाले प्रत्येक एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही सही जगह पहुंच पाते हैं, उन्होंने सही कहा था। लेकिन अब हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं।

गौरतलब है कि भाजपा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीवीएफ) ने संयुक्त रूप से यह रैली आयोजित की थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, कर्बी समुदाय और पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे बोडो लोगों को जनजातीय दर्जा दिया जाएगा। प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। श्री मोदी ने कहा, उन्होंने निर्देश दिया है कि पूर्वोत्तर से युवाओं को दिल्ली पुलिस में भर्ती किया जाना चाहिए और प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। कोकराझार में एक केंद्रीय तकनीकी संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। सियालदह-गुवाहाटी कंचनजंगा एक्सप्रेस को बराक घाटी तक विस्तारित किया जाएगा, जबकि धुबुरी स्थित रूपसी हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना अपने नियंत्रण में लेगी।

गुवाहाटी (असम)

कांग्रेस से मांगा 60 वर्षों का हिसाब

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को कोकराझार और गुवाहाटी में रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर लोगों से किए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया श्री मोदी ने असम के कर्बी और बोडो समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा देने का ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का फोकस उत्तर पूर्व पर है। यहां के युवकों को दिल्ली पुलिस में भर्ती का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूर्व की ओर काम करो (एक्ट ईस्ट) नीति लाई है। इस इलाके के विकास

के लिए पहली जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की है। श्री मोदी ने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार से भेजे जाने वाले प्रत्येक एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही सही जगह पहुंच पाते हैं। राजीव गांधी ने सही कहा था। लेकिन अब दिल्ली राज्य सरकारों से हिसाब मांगती है। उन्होंने जब विकास कोष को लेकर जवाब मांगा, तो असम समेत पूर्वोत्तर में कई अन्य राज्य सरकारें परेशान हो गईं।

प्रधानमंत्री ने कोकराझार स्थित सेंट्रल टेक्निकल इंस्टिट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने, सियालदाह-गुवाहाटा कंचनजंघा एक्सप्रेस बराक वैली तक चलाए जाने और रूपसी एयरपोर्ट को एयरफोर्स के नियंत्रण में लिए जाने की भी घोषणा की। श्री मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी में 6,000 छात्रों को भी संबोधित किया। 15 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने यहां कुछ नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल तक देश पर शासन किया जो यहीं से चुने गए थे। लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की अनदेखी की गई है।

बुनियादपुर (प.बं.) में भाजपा रैली

ममता की टीएमसी सरकार अपराधियों को बचा रही : नितिन गडकरी

केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मालदा हमले पर ममता सरकार पर हमला बोलते हुए अपराधियों को शरण देने पर कोर्ट कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधान सभा चुनावों में टीएमसी का सत्ता से बाहर किया जाए और राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए भाजपा सरकार को लाया जाए।

जब आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो आप ने गरीब नागरिकों की रक्षा करने की शपथ ली थी। परन्तु आप गरीब नागरिकों को बचा नहीं रही है जिनमें घरों को लूटा जा रहा है और पुलिस स्टेशनों को आज लगाई जा रही है एवं हिंसा पैदा की जा रही है। श्री गडकरी ने 18 जनवरी 2016 को दक्षिण दीनाजपुर जिले में बुनियादपुर में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार पर वोट बैंक राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो पार्टी अपराधियों तथा घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, नरेन्द्र मोदी सरकार आपके साथ है। हम ऐसी सरकार नहीं है जो अपराधियों के सामने झुक जाएगी। हम ऐसी पार्टी है कि जो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय ने केन्द्र से मालदा हिंसा के 3 जनवरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

तमिलनाडु

प्रकाश जावडेकर बने चुनाव प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह ने 18 जनवरी को तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हेतु निम्नलिखित को चुनावों के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है-

1. श्री प्रकाश जावडेकर (प्रभारी)
2. श्री पीयूष गोयल (सह-प्रभारी)

केरल

जेपी नड्डा बने चुनावी प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह ने 18 जनवरी को केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव-2016 हेतु निम्नलिखित को चुनावों के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है:-

1. श्री जे.पी. नड्डा (प्रभारी)
2. श्री राजीव प्रताप रूडी (सह-प्रभारी) ■